vinetur

दो साल में 1 लाख नौकरियां गंवाने के बाद ब्रिटेन का हॉस्पिटैलिटी उद्योग नेशनल इंश्योरेंस में कटौती की मांग कर रहा है

UKHospitality का कहना है कि पेरोल की बढ़ती लागत उस क्षेत्र के लिए खतरा है, जो 16 से 24 वर्ष के लोगों की पहली नौकरियों में 31% का योगदान देता है।

गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026



ब्रिटेन का हॉस्पिटैलिटी उद्योग इस महीने के बजट में नियोक्ताओं के नेशनल इंश्योरेंस खर्च में कटौती की मांग कर रहा है। उसका कहना है कि युवाओं को काम की दुनिया में प्रवेश दिलाने में क्षेत्र की अहम भूमिका बढ़ते करों और परिचालन खर्चों के कारण कमजोर पड़ रही है।

क्षेत्र के प्रमुख व्यापारिक संगठन UKHospitality ने कहा कि Office for National Statistics के आंकड़ों के नए विश्लेषण के अनुसार, हॉस्पिटैलिटी कारोबारियों ने पिछले दो वर्षों में करीब 1 लाख नौकरियां गंवाई हैं। संगठन के मुताबिक, इसी अवधि में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में कुल जितनी नौकरियां खत्म हुईं, उनमें यह आंकड़ा 45% है।

संगठन ने कहा कि इन नौकरियों का जाना खास तौर पर इसलिए अहम है, क्योंकि रेस्तरां, पब, बार, होटल और हॉस्पिटैलिटी के अन्य कारोबार देश में पहली नौकरी देने वाले सबसे बड़े स्रोतों में शामिल हैं। उसके विश्लेषण के अनुसार, 16 से 24 वर्ष के लोगों की पहली नौकरियों में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी 31% है और ब्रिटेन में काम कर रहे सभी युवाओं में से 18.2% को यह रोजगार देता है। UKHospitality ने कहा कि इस क्षेत्र में हर साल युवा कर्मचारियों के लिए करीब 3 लाख पद सृजित होते हैं, लेकिन उसका तर्क है कि जब तक सरकार रोजगार की लागत कम नहीं करती, ये अवसर जोखिम में हैं।

संगठन मंत्रियों से अनुरोध कर रहा है कि मौजूदा संसद का कार्यकाल खत्म होने तक हॉस्पिटैलिटी कारोबारियों के लिए नियोक्ता नेशनल इंश्योरेंस योगदान की सीमा चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर £10,000 कर दी जाए। इस मांग का मकसद ऐसे समय में नियोक्ताओं की पेरोल लागत कम करना है, जब कई कारोबारियों का कहना है कि उनके मुनाफे पर पहले से ही भारी दबाव है।

UKHospitality के मुख्य कार्यकारी Allen Simpson ने कहा कि करों के दबाव और लागत में महंगाई के मिले-जुले असर ने युवा कर्मचारियों को काम पर रखने की क्षेत्र की क्षमता को नुकसान पहुंचाया है। उनके मुताबिक, हॉस्पिटैलिटी कंपनियों पर पिछले दो वर्षों में £5bn से अधिक की अतिरिक्त लागत आई है। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र अपने कर-पूर्व मुनाफे का 82% कारोबार करों के रूप में चुकाता है। UKHospitality के अनुसार, किसी भी उद्योग में यह सबसे बड़ा हिस्सा है।

Simpson ने कहा कि इस मुद्दे को चांसलर John Healey के पहले बजट में संबोधित किया जाना चाहिए, जो बुधवार, 28 अक्टूबर को पेश होना तय है। उनका तर्क था कि बजट में ऐसे श्रम-प्रधान कारोबारों को समर्थन देने की नीति की दिशा में बदलाव का संकेत होना चाहिए, जहां बड़ी संख्या में युवा और कम वेतन पाने वाले कर्मचारी काम करते हैं।

UKHospitality की चेतावनी ऐसे समय आई है, जब उद्योग के कई नियोक्ता अब भी मुश्किल कारोबारी माहौल से जूझ रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी कारोबारियों पर कर्मचारियों की लागत बढ़ने का असर खास तौर पर अधिक पड़ता है, क्योंकि कुल खर्च में मजदूरी का बड़ा हिस्सा होता है। उन्हें ऊर्जा बिल, खाद्य महंगाई, किराये, कारोबार दरों और उधारी की लागत का दबाव भी झेलना पड़ता है। व्यापारिक संगठनों का महीनों से कहना है कि कई प्रतिष्ठान अब काम के घंटे घटाए बिना, भर्ती कम किए बिना या निवेश टाले बिना इन बढ़ती लागतों को बर्दाश्त नहीं कर सकते।

संगठन ने मौजूदा रोजगार नुकसान को सीधे इन दबावों से जोड़ा। उसने कहा कि युवाओं को काम के अवसर देने की क्षेत्र की क्षमता पर पहले से ही दबाव है और यदि सरकार ने कदम नहीं उठाया तो स्थिति और बिगड़ सकती है। Simpson ने कहा कि कारोबारी नहीं चाहते कि और नौकरियां या अवसर खत्म हों। उन्होंने मंत्रियों से कर्मचारियों को काम पर रखने की लागत घटाने की अपील की, ताकि क्षेत्र फिर से अधिक आसानी से भर्ती कर सके।

व्यापारिक संगठन ने इस मुद्दे को श्रम बाजार की व्यापक समस्या के हिस्से के रूप में भी पेश किया। उसने कहा कि हॉस्पिटैलिटी उन युवाओं की संख्या घटाने में मदद कर सकता है जो शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण में नहीं हैं। ब्रिटेन में ऐसे युवाओं को अक्सर NEETs कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि उद्योग बड़ी संख्या में शुरुआती स्तर की नौकरियां और लचीले कार्य-समय देता है। कई युवा कर्मचारियों के लिए हॉस्पिटैलिटी की नौकरियां श्रम बाजार में पहला कदम होती हैं और उनसे ग्राहक सेवा, टीमवर्क तथा प्रबंधन का अनुभव मिलता है।

कर राहत की मांग के साथ UKHospitality ने स्थानीय आर्थिक विकास और हाई स्ट्रीट को फिर से सक्रिय करने पर केंद्रित व्यापक नीतिगत पैकेज भी पेश किया। इस सप्ताह की शुरुआत में संगठन ने केंद्र सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों के लिए एक खाका प्रकाशित किया, जिसमें नियामकीय बाधाएं घटाने और व्यावसायिक इलाकों को फिर से उबरने में मदद देने के लिए 33 सिफारिशें शामिल थीं। प्रस्तावों में कारोबार दरें, बुनियादी ढांचा, लाइसेंसिंग, नियोजन, किराया और कौशल शामिल थे।

अन्य उपायों के साथ संगठन ने नियोजन मंजूरियों में तेजी लाने, लाइसेंसिंग नियमों में बदलाव करने और हॉस्पिटैलिटी

प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अधिक विस्तार करने की मांग की। उसका कहना था कि कम कर लागत के साथ ये बदलाव कारोबारियों के लिए प्रतिष्ठान खोलना, विस्तार करना और कर्मचारियों की भर्ती करना आसान बनाएंगे।

यह बहस केवल रोजगार के आंकड़ों से आगे भी मायने रखती है, क्योंकि पब, बार और रेस्तरां पेय कारोबार के केंद्र में हैं। यदि संचालकों पर कर और श्रम लागत का दबाव बढ़ता रहा, तो इससे मुनाफा घट सकता है, प्रतिष्ठानों के बीयर, वाइन और स्पिरिट्स पर खर्च पर सीमा लग सकती है और पेय आपूर्ति श्रृंखला के कुछ हिस्सों में मांग कमजोर हो सकती है। कर्मचारियों की संख्या घटने से खुलने के घंटे, सेवा क्षमता और बिक्री की मात्रा भी प्रभावित हो सकती है, खासकर उन कारोबारों में जहां पेय पदार्थ राजस्व का बड़ा स्रोत हैं।

सरकार ने UKHospitality के नवीनतम प्रस्ताव पर अब तक सार्वजनिक रूप से कोई जवाब नहीं दिया है। बजट पर खुदरा, अवकाश और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के नियोक्ताओं की करीबी नजर रहने की उम्मीद है। उनका कहना है कि श्रम-प्रधान क्षेत्रों पर कर और अनुपालन लागत का अनुपातहीन बोझ पड़ रहा है।

फिलहाल UKHospitality यह तर्क रख रहा है कि हॉस्पिटैलिटी को केवल उपभोक्ताओं से सीधे जुड़े उद्योग के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार देने वाले इंजन के रूप में भी देखा जाना चाहिए। उसका मुख्य तर्क है कि यदि सरकार अधिक युवाओं को रोजगार दिलाना और कस्बों तथा शहरों के केंद्रों को मजबूत करना चाहती है, तो उसे उन कारोबारों में लोगों को काम पर रखने की लागत घटानी होगी जो युवाओं को उनकी पहली नौकरी देते हैं।